3135. [*Transferred to the 20th December, 1991.*]

Complaint of black marketing in handloom

3136. KUMARI SYEEDA KHATUN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the NCCF has been entrusted with the task of distribution of Handloom meat for the vulnerable section of the society;

(b) whether it is also a fact that Government provide subsidy of about Rs. 4,000 per bale on the Handloom;

(c) whether Government have received serious complaints of blackmarketing of Handloom between 1988-90 with the connivance of officers of NOCF, Kanpur, Uttar Pradesh Handloom Corporation and the inspotes;

(d) whether the stocks found way into the hands of unscrupulous persons thereby cheating Government of several crores of rupees;

(e) if so, whethe Government had enquired into the matter; and

(f) if so, the outcome thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) National Consumers Cooperative Federation of India is one of the approved distribution agencies in the matter of distribution of Janata Cloth produced in the handloom sector.

(b) Government of India subsidises the production of Janta Cloth at the rate of Rs. 3.40 per square metre.

(c) to (f) Yes Sir. A complaint was received alleging malpractices in the scale of Janata Cloth involving some employees of NCCF. This aspect is being investigated by NCCF and a final report is awaited.

1981 की जनगणना के आधार पर कोटे का आबंटन

3137. **श्री राधवजी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों को चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं और खाद्य तेलों के आवंटन का आधार 1981 की जनगणना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मापदण्ड में परिवर्तन किया जाएगा और क्या 1991 की जनगणना के आंकड़ों को इस प्रकार के आवंटन का आधार बनाया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग). जी, नहीं । खाद्यान्नों (चावल व गेहूं) का आवंटन, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों की मांग, केन्द्रीय पूल में स्टाक की स्थिति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का परस्पर आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है । आयातित खाद्य तेल का आवंटन केन्द्रीय सरकार के पास मात्रा उपलब्ध होने पर किया जाता है ।

इस समय मिट्टी के तेल का आवंटन कमोबेश गत वर्ष के इतने ही महीने के स्तर पर बनाये रखा गया है ।

लेवी चीनी का आवंटन आमतौर पर 1-10-1986 को अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के समान प्रतिमान के आधार पर किया जाता है । सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के आवंटनों में अगस्त से दिसम्बर, 1991 के महीनों के लिए 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की गई थी ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और इनका प्रयोजन राज्यों।संघ राज्य क्षेत्रों को सम्पूर्ण मांग को पूरा करना नहीं होता है ।

दिल्ली में उचित दर की दुकानें

3138. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में चल रही उचित दर की दुकानों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या ये दुकानें उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की सप्लाई उचित दर पर करती हैं ; और

(ग) इस समय मुख्य खाद्यान्नों की दरें किस प्रकार तय की गई हैं ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) 1–12–1991 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में 3548 उचित दर की दुकानें हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उचित दर की दुकानों के जरिए बेचे जाने वाले खाद्यान्नों के खुदरा बिक्री मूल्य समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में लाभ का मार्जिन और ढुलाई तथा रख-रखाव प्रभारों को जोड़कर किये जाते हैं ।

Defence Exports

3139. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI KAMAL MORARKA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what target has been fixed for defence exports including arms/weapons during the current year;

(b) what is the vaule of our total defence production and how much of it is etxported;

(c) what steps have so far been taken to boost such exports; and

(d) what is the amount of foreign exchange expected to be earned through such exports during the current year?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) Export target fixed for Defence Production units during the current year is Rs. 104 crores.

(b) The value of production by the Ordnance Factory Board and Defence Public Sector Undertakings during 1990-91 was Rs. 6043.15 crores. Earnings from export (including deemed exports) by Defence production units during 1990-91 were Rs. 78.94 crores.

(c) The steps taken to boost defence exports include policy and procedural liberalisations, marketing efforts through our missions and by the production apencies as well as other export agencies and sales/publicity measures such as participation in foreign exhibitions, exchange of delegations etc.

(d) It is expected that the foreign exchange earnings will be as per the target fixed i.e. Rs. 104 crores.

Recruitment of Women in Defence Forces

3140. SHRI NARREDDY THULASI REDDY:
SHRI SYED SIBTEY RAZI:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision regarding recruitment of women in Defence Services; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) and (b) The Government have recently approved a proposal for the recruitment of women in the officer ranks of the Education, Logistics and the Law Branches of the Indian Navy. Induction of women in the officer cadre of the Non-Technical Ground Duty